

जी 20 और भारत*

दुवुरी सुब्बाराव

मैं फोरम ऑफ फ्री इन्टरप्राइज और श्री मीनू श्राफ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ए.डी.श्राफ मेमोरियल व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया। यह मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात है।

ए.डी.श्राफ

2. ए.डी.श्राफ की कोई खास पृष्ठभूमि न होने के बावजूद, वे अपने समय के वित्तीय क्षेत्र में देश के श्रेष्ठ और सम्मानित व्यवसायियों में से एक के रूप में उभरे थे। इन्होंने टाटा सन्स के बोर्ड में वित्तीय सलाहकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की तथा बाद में वे न्यू इण्डिया एश्योरेन्स और बैंक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकृत होने के पहले उनके अध्यक्ष बने। जब एक समय नेहरूवियन सामाजवादी विचारधारा आर्थिक विचारधारा पर हावी थी, तब फेल्डमैन-महलनोबिस ने विकास के प्रतिमान बनाए थे और सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर था, उस समय श्री श्राफ ने ही बाजार अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाए जाने की वकालत करने का साहस दिखाया था। ये वही बुनियादी विचार थे जिनसे 1944 के बांबे प्लान को प्रेरणा मिली जिसके सह-लेखकों में से एक श्री श्राफ भी थे।

3. रिजर्व बैंक ने बहुत पहले ही 1953 में श्राफ की विशेषज्ञता और उनकी नवोन्मेषी विचारधारा को पहचाना और उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसके अध्ययन का विषय यह था कि निजी क्षेत्र में वित्त प्रवाह को कैसे बढ़ाया जाए। श्राफ समिति की सिफारिशों ने वित्तीय क्षेत्र में संस्थान बनाने का आधार तैयार करने में प्रमुख भूमिका अदा की - आईसीआईसीआई और बाद में आईडीबीआई को विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया, 1960 के शुरुआती दिनों में डीआईसीजीसी के रूप में एक निक्षेप बीमा निगम अस्तित्व में आया और निवेश में छोटी बचतों को शामिल करने के लिए माध्यम के रूप में यूनिट ट्रस्ट की स्थापित करने के समिति के सुझाव के अनुसार ही बाद में यूटीआई की स्थापना की गई।

4. श्राफ समिति की सिफारिशें मौलिक थीं और उन्हें महत्त्व प्राप्त हुआ। शायद, यह बात कम लोग जानते हैं कि ए.डी. श्राफ रिजर्व बैंक

के ऐसे उप गवर्नर थे जो रिजर्व बैंक में कभी नहीं रहे। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑस्बार्न स्मिथ ने 1936 में उन्हें उप गवर्नर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था किन्तु ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जिसके पीछे यह कारण बताया गया कि ब्रिटिश सरकार को लगता था कि श्राफ तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के नजदीकी थे। यह बिड़बना है कि जिन्हें एक ओर कांग्रेस का अर्थशास्त्री माना गया था, वहीं ये दूसरी और तीसरी योजना अवधि के दौरान कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीति के सबसे प्रखर आलोचकों में से एक थे।

5. स्पष्ट रूप से, समय से आगे की सोच रखने वाले ए.डी. श्राफ ने उदाररीकृत, बाजार-प्रेरित वातावरण में राष्ट्र निर्माण के लिए निजी निवेश के महत्त्व को समझा था। जैसे प्रत्येक अच्छे विचार को समय की प्रतिक्षा रहती है, वैसे ही, उदाररीकरण, जिसकी इन्होंने पूरजोर वकालत की थी, नब्बे के प्रारंभिक दिनों अर्थात् इनकी मृत्यु के पच्चीस साल बाद तक देश में नहीं आया था।

6. 90 के दशक के दौरान हमारे द्वारा शुरू किया गया आर्थिक उदाररीकरण, जो अभी भी चल रहा है, का उद्देश्य भारत को शेष संसार के साथ जोड़ना था। पिछले दस सालों में जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत का दोतरफा प्रवाह दोगुना हो गया: जीडीपी के अनुपात के रूप में हमारा दोतरफा चालू और पूंजीगत प्रवाह दोगुना से भी अधिक हो गया। वैश्विक वित्तीय संकट और अब यूरोजोन संकट से प्राप्त अनुभव से ज्ञात हुआ है कि भले ही हमें एकीकरण से लाभ हुआ हो, किन्तु इस एकीकरण के कारण हम वैश्विक आघातों के प्रति असुरक्षित भी हो गए हैं।

7. भारत द्वारा वैश्वीकरण को अपनाना और विशिष्ट संक्रमण जिससे अर्थव्यवस्था 1990 के आर्थिक सुधार के बाद गुजरी है, ए.डी. श्राफ जैसे दूरदर्शी और दृढ़ विश्वास रखने वाले प्रतिष्ठित विचारक की बात को प्रामाणित करती है। मुझे नहीं लगता है कि उनके जैसे दूरदर्शी व्यक्ति को याद करने के लिए इससे बेहतर और कोई उपाय हो सकता था कि हम वैश्विक आर्थिक नीति बनाने में भारत की प्रमुख और बढ़ती भूमिका के बारे में चर्चा करें। विशेष रूप से, मैं इस बड़े अंतरराष्ट्रीय फोरम में जी 20 और भारत के हितों पर फोकस करूंगा।

* भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. दुवुरी सुब्बाराव द्वारा इण्डियन मर्चेन्ट चैंबर, मुंबई में 20 नवंबर 2012 को दिया गया 46वां ए.डी. श्राफ मेमोरियल व्याख्यान।

जी 20

8. हम सभी जानते हैं कि जी 20 वित्तीय संकट से सीधे लड़ रहा है - 2008/09 का वैश्विक वित्तीय संकट और 2010 से यूरोजोन संकट जिसने वैश्विक संवृद्धि और कल्याण पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। वास्तव में, जब इस संकट का इतिहास लिखा जाएगा तो अप्रैल 2009 में लंदन में सम्पन्न जी 20 सम्मेलन को एक निर्णायक बिन्दु के रूप में माना जाएगा जब संसार के नेताओं ने असाधारण संकल्प और एकता का परिचय दिया था। निश्चित रूप से उनमें मत भिन्नताएं थीं किन्तु उन्हें बहस और चर्चा के जरिए हल कर लिया गया और एक बीच का रास्ता निकाला गया ताकि संकट को समाप्त किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप संकट से निपटने के लिए सर्वसम्मत पैकेज तैयार किया गया जिसमें देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों से जुड़े उपाय शामिल किए गए किन्तु इन सभी को आपसी तालमेल और जहां अधिक आवश्यक था वहां एक साथ लागू किया जाना था। संकट संबंधी समाधान के उपायों की संपूर्ण कड़ियों - निभावी मौद्रिक रुझान, राजकोषीय प्रोत्साहन, ऋण और जमा गारंटियां, पूंजी आपूर्ति, आस्ति क्रय, मुद्रा स्वैप, बाजारों को खुला रखना - को अलग-अलग मात्रा में जी 20 के पैकेज से लिया गया।

9. पांच वर्षों से संकट अभी भी हम पर बना हुआ है : केवल इसका मूल बिन्दु और इससे प्रभावित होने वाले देश बदले हैं। इन पांच वर्षों के दौरान विश्व में जी 20 की सदस्यता वाले देशों के भीतर भी कुछ प्रमुख मुद्दों पर असहमति बन गई है। इसलिए चिंता और आशंका है कि एकता और जिस उद्देश्य के लिए जी 20 देशों में पहले सहमति बनी थी वह अब कम हो रही है।

10. इस पर मेरी खुद की राय है कि इन मतभेदों को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि संसार में अलग-अलग राष्ट्र हैं, यहां वैश्विक अर्थव्यवस्था की सामान्य व्यवस्था नहीं है। जब कार्य का दायरा इतना बड़ा है और देश स्तर की बाध्यताएं वैश्विक हित के साथ टकराएंगी ही, तो उनमें मतभेद होना स्वाभाविक है। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन मदभेदों को यह मानते हुए दूर करने में समर्थ हैं कि वैश्वीकृत संसार में कोई भी देश अलग नहीं रह सकता। कहीं भी होने वाली घटनाएं अन्य अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता सभी के हित में है और सर्वोत्तम वैश्विक समाधान के लिए संसार को निर्देशित करने हेतु जी 20 के अलावा और कोई प्रभावीशाली फोरम नहीं हो सकता।

11. इस संदर्भ का निर्धारण करने के पश्चात अब मैं निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करूंगा:

- जी 20 क्या है और यह कैसे कार्य करता है?
- जी 20 क्यों महत्वपूर्ण है?
- जी 20 की कार्यसूची में प्रमुख मुद्दे और उनके प्रति भारत की चिंता क्या रही है/है।
- जी 20 के लिए भावी चुनौतियां क्या हैं?

जी 20 क्या है?

12. जी 20 एक औपचारिक समूह है जिसमें यूरोपियन संघ के अलावा अन्य 19 सदस्य देश हैं जिनका वैश्विक जीडीपी में 90 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार में 80 प्रतिशत और वैश्विक जनसंख्या का दो-तिहाई हिस्सा है।

13. प्रचलित मत के विपरीत, जी 20 कोई नया अंतरराष्ट्रीय समूह नहीं है जिसे वैश्विक वित्तीय संकट के कारण बनाया गया। वास्तव में, इसकी स्थापना पूर्व में हुए संकट अर्थात् 1997 के एशियन संकट के कारण हुई थी। यद्यपि, इसकी बैठकें 1997 से नियमित रूप से हो रही हैं, किन्तु इसका महत्व और विश्वनीयता वैश्विक वित्तीय संकट के परिणाम स्वरूप उस दौरान और अधिक बढ़ी जब यह वित्त मंत्रियों के फोरम से ऊंचा उठाकर लीडर्स का फोरम बन गया।

14. जी 20 का अध्यक्ष पद प्रत्येक वर्ष देश-वार बदलता रहता है। अध्यक्ष देश कार्यसूची बनाने और उसे आगे बढ़ाने की शुरुआत करता है। जी 20 के नेता साल में एक बार शिखर सम्मेलन में मिलते हैं¹। इसके अतिरिक्त साल में दो बार जी 20 के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक होती है। सभी बैठकों का आयोजन अध्यक्ष देश द्वारा किया जाता है। जी 20 की बैठकों में विश्व बैंक के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक भाग लेते हैं, फलस्वरूप यह सुनिश्चित करते हैं कि जी 20 की गतिविधियों को जहां आवश्यक हो, ब्रेटन वूड्स इन्स्टीट्यूट की कार्यसूची के साथ जोड़ा जाए। जी 20 की बैठकों में ओईसीडी, यूएनडीपी और क्षेत्रीय विकास बैंक जैसी अन्य संस्थाओं को भी आमंत्रित किया जाता है।

¹ संकट के दौरान जी 20 के नेताओं की बैठक वर्ष के दो बार हुई। अब फिर से मानक के अनुसार बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। संकट के पश्चात, जी 20 के नेताओं के सात शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं: वाशिंगटन (नवंबर 2008), लंदन (मार्च 2009), पिट्सबर्ग (अक्टूबर 2009), टोरंटो (जून 2010), सियोल (नवंबर 2010), केन्स (नवंबर 2011) और लास कैबोस (जून 2012)।

जी 20 क्यों महत्वपूर्ण है?

15. जी 20 को कम-से-कम दो तरह से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कूटनीति में वाटरमार्क के रूप में देखा जा सकता है।

16. पहला, यह ब्रेटन वूड्स प्रणाली की वैश्विक अभिशासन की पुरानी विभाजक प्रणाली, जिसकी मुख्य विशेषता प्रमुख विकसित देश (जी 8) जो दाता होते थे और विकासशील देश (जी 77) जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता के प्राप्तकर्ता होते थे, के बीच कम संप्रेषण और अधिक दुर्भाव थी, से एक कदम आगे है। उनकी धारणा में मतभेद अभी भी बना हुआ किन्तु अब दाता-प्राप्तकर्ता समीकरण में, एक-दूसरे के नजरिए का बेहतर मूल्यांकन करने में और जी 20 रिपोर्ट और घोषणाओं, जिसके प्रति देशों के समूह प्रतिबद्ध हैं, के जरिए प्रारंभिक नए अंतरराष्ट्रीय क्रम पर सहमति बनाने में बहुत अधिक परिवर्तन देखा जा सकता है।

17. अंतरराष्ट्रीय अभिशासन की इस नई प्रणाली को कुछ समय से तैयार किया जा रहा था। बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं विशेष रूप से ब्रिक्स² लंबे समय से ओईसीडी देशों की तुलना में तेजी से विकास कर रही हैं और लगातार महत्वपूर्ण बनती जा रही हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वैश्वीकरण के प्रभावी प्रबंधन के लिए किसी भी बहुपक्षीय आर्थिक परामर्शी प्रक्रिया का उस प्रक्रिया में समावेश होना जरूरी था। वैश्विक संकट के पहले भी, जी 8 ने बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं अर्थात् जी 5 (ब्राजील, भारत, चीन, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रिका) को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करना आवश्यक समझा था किन्तु इन अर्थव्यवस्थाओं को मात्र कुछ चुनिन्दा सत्रों हेतु ही आमंत्रित किया जाता था जिसे हेलीगंडम प्रक्रिया कहा गया। वैश्विक वित्तीय संकट ने वैश्विक आर्थिक अभिशासन में प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार अस्थिरता का स्रोत रही कई बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को अब स्थिरता और विकास के बिन्दु के रूप में देखा जा रहा है।

18. जी 20 के अद्वितीय होने की दूसरी वजह प्रणालीगत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की समष्टि-आर्थिक नीतियों में समन्वय बनाने का उनके द्वारा किया गया प्रयास है जहां ऐसे विश्व में उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां राष्ट्रीय समष्टिआर्थिक नीतिगत साधनों को व्यापार और वित्तीय बाजारों के माध्यम से त्वरित वैश्विक

एकीकरण द्वारा दुर्बल किया जा रहा है। संकट संबंधी उनके द्वारा किए गए संयुक्त और समन्वित नीतिगत उपाय के बाद जी 20 ने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय ढांचे को सुधारने के प्रयास शुरू किए हैं और साथ ही मजबूत, टिकाऊ और संतुलित वैश्विक संवृद्धि के लिए लंबे समय से चली रहीं संरचनागत बाधाओं को दूर करने के प्रयास शुरू किए और आगे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया 'पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया' की शुरुआत की जिसे जी 20 द्वारा किए महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जाता है। इस प्रक्रिया की सफलता वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जरूरी है जिस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा।

जी 20 की कार्यसूची के मुख्य मुद्दे

19. मैं अब 2008/09 के वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने के बाद जी 20 की शुरुआत और महत्व के संदर्भ में जी 20 की कार्यसूची से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करूंगा। जहां उचित होगा वहां मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा करूंगा।

वैश्विक पुनर्संतुलन बनाना

20. मैं सबसे पहले वैश्विक असंतुलन पर चर्चा करना चाहता हूँ। लगभग सभी इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक वित्तीय संकट के मूल कारणों में वैश्विक असंतुलन का बढ़ना भी एक कारण है। वैश्विक असंतुलन वह चाहे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 'ज्यादा खपत' या उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 'अधिक बचत' के कारण हो, संकट के मूल कारण थे। वैश्विक वित्तीय स्थिरता को पुनः पटरी पर लाने के लिए असंतुलन को कम करना एक आवश्यक शर्त है।

21. वैश्विक असंतुलन से संबंधित संकट के बाद की चर्चा के तीन परस्पर-संबद्ध पहलू हैं। पहला पहलू वैश्विक पुनर्संतुलन में विनिमय दर की भूमिका है। दूसरा पहलू उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीगत प्रवाह से संबंधित है जो असंभव तीन कारकों को नियंत्रित करने की प्रमुख चुनौती पैदा करती है और तीसरा पहलू समायोजन प्रक्रिया से संबंधित ढांचा है। अब मैं एक-एक कर इन पर चर्चा करूंगा।

22. पहला, विनिमय दरों की भूमिका - बाह्य असंतुलनों के समाधान का एक प्रमुख साधन। वैश्विक पुनर्संतुलन के लिए जरूरी है कि घाटे की अर्थव्यवस्थाएं बचत अधिक और खपत कम करें। वे संवृद्धि के लिए बाह्य मांग पर अधिक निर्भर होते हैं जिसके लिए उनकी मुद्राओं का वास्तविक मूल्यहास आवश्यक होता है। अधिशेष वाली अर्थव्यवस्थाओं को इन प्रयासों के विपरीत चलना होगा - वे बचत कम और खर्च अधिक करें और उन्हें बाह्य मांग की अपेक्षा देशी मांग

² ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रिका शामिल हैं।

पर निर्भर होने की आवश्यकता होगी। उनके लिए यह आवश्यक होगा की वे अपनी मुद्राओं को मजबूत होने दें। यद्यपि समस्या यह है कि घाटे और फायदे वाली अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए गए समायोजन एक जैसे होते हैं उन्हें मिलने वाले प्रोत्साहन भिन्न होते हैं। मुद्रा तनाव को नियंत्रित करने के लिए विनिमय दरों को अर्थव्यवस्था के मूलतत्त्वों के अनुरूप रखने पर आपसी समझौते की जरूरत होगी और ऐसी सहमति की जरूरत होगी कि मुद्रा हस्तक्षेप का सहारा व्यापार नीति के साधन के रूप में नहीं, बल्कि समष्टि स्थिरता से संबंधित अड़चनों को दूर करने के लिए ही लिया जाना चाहिए।

23. अब मैं वैश्विक असंतुलन के दूसरे पहलू अर्थात् पूंजी प्रवाह पर चर्चा करूंगा। पूंजी प्रवाह की समस्या विकसित अर्थव्यवस्था के केन्द्रीय बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में मुद्रा आपूर्ति करने के परिणाम स्वरूप उस समय प्रबल हो गई जब वैश्विक प्रणाली में अधिक मात्रा में चलनिधि प्रगतिशील उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के पास आ गई। अधिक पूंजी प्रवाह के कारण उत्पन्न हुई बहुत बड़ी समस्या मौद्रिक नीति का निष्क्रिय होना, मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी होना और प्रतिस्पर्धा खोना है। प्रत्याशित पूंजी प्रवाह के कारण आस्ति और वस्तुओं के मूल्य में तेज वृद्धि हुई जिसके चलते वित्तीय और आर्थिक दोनों में स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है।

24. जी 20 में पूंजी प्रवाह पर चर्चा के दौरान लोकप्रिय रूप से किन्तु गलती से इसे 'मुद्रा युद्ध' के रूप में लिया गया। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने मुख्य रूप से दो मुद्दे उठाए। पहला, बहुत अधिक अनियमित और अस्थिर पूंजी प्रवाह का कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अधिक मात्रा में मुद्रा आपूर्ति करना है, इसलिए समायोजन का भार बांटना चाहिए। दूसरा, पूंजी नियंत्रण को प्रत्याशित पूंजी प्रवाह के प्रति वैध और स्वीकार्य बचाव के रूप में मानना चाहिए।

25. जी 20 ढांचे और पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया (एमएपी) के मुख्य मुद्दों में वैश्विक असंतुलन और उसे सही करना शामिल था। एमएपी का उद्देश्य बाह्य क्षेत्र से संबंधित उन नीतियों के प्रति देशों को प्रतिबद्ध बनाना है जो उन्हें वैश्विक स्तर पर मजबूत, टिकाऊ और संतुलित संवृद्धि की ओर ले जाए। यह माना जाता है कि वैश्विक असंतुलन, विशेष रूप से रिजर्व के निर्माण और अवमूल्यित विनिमय दरों के कारण निर्मित हुआ असंतुलन, वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए खतरा है क्योंकि इसमें अव्यवस्थित ढंग से अनविडिंग की संभावना होती है।

26. चीन की विनिमय दर नीतियां जी 20 में चर्चा का मुख्य केन्द्र थीं। चीन का चालू खाता अधिशेष (उसकी जीडीपी की तुलना में)

संकट पूर्व के स्तर से कम हो गया है और चीन की वास्तविकप्रभावी विनियम दर भी 2005 से बढ़ी है। फिर भी, यह माना जाता है कि इसमें अभी और बढ़ोतरी होना चाहिए। तथापि, इस बीच, तेल का उत्पादन करने वाले देशों (मुख्यतः ओपेक, रूस और नार्वे) के संचयी अधिशेष में बढ़ोतरी हुई है और अब वैश्विक चालू खाता अधिशेष का अधिकांश हिस्सा इन्हीं का है। जहां संकट के बाद की अवधि के दौरान वैश्विक असंतुलन में कमी आई है, वहीं उनकी प्रकृति और संरचना में लगातार विस्तार हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि जी 20 में एमएपी संरचना, प्रकृति, वैश्विक असंतुलन के प्रसार और उनके प्रभाव पर निगरानी रखता है और उनके अंतर्निहित कारणों के संबंध में कार्य करता है।

27. अब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक असंतुलन की समस्या के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करूंगा। वैश्विक असंतुलन सृजित करने या उसका विस्तार करने में भारत की कोई भूमिका नहीं है। जितना अधिक हम अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहते हैं, उतना अधिक हमें लगता है कि यह बेहतर उत्पादकता से आनी चाहिए न कि बनावटी नपीतुली विनिमय दरों से। हमारी विनियम दर मुख्यतः बाजार से संचालित होती है और हम मुख्यतः दर की अस्थिरता को नियंत्रित करने और समष्टि-आर्थिक अस्थिरता को रोकने लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, हमारा चालू खाते का घाटा काफी अधिक है जो कि हाल ही में, हमारे पिछले रिकार्ड की तुलना में बढ़ गया है। हमें सीएडी को वित्तपोषण के लिए पूंजी प्रवाह की जरूरत है। इसके लिए हमारी पहली पसंद ऋण प्रवाह की तुलना में इक्विटी प्रवाह, पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में प्रत्यक्ष निवेश और अल्पावधि की तुलना में दीर्घावधि निवेश हैं और हम योजनाबद्ध तरीके से अपना पूंजी खाता खोलने की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं; उभरती वैश्विक स्थिति के लिए यह योजना स्वयं ही बहुत नपी-तुली है। संक्षिप्त रूप से कहे तो *हमारी नीति 'धीरे-धीरे गति बढ़ाने की है।'*

28. जी 20 फ्रेमवर्क 'एमएपी' कार्यशील समूह में कनाडा के साथ भारत की साझी अध्यक्षता है। इससे भारत के पास न केवल वैश्विक प्रयासों के समष्टि और व्यष्टि परिणामों की प्रारंभिक समीक्षा प्राप्त करने अवसर है बल्कि इन प्रयासों में सक्रिय योगदान करने का भी अवसर है। इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश की भूमिका से संबंधित भारत के सुझाव वैश्विक सुधार में और पुनर्संतुलन बनाने में भूमिका अदा कर सकते हैं। सह-अध्यक्ष के रूप में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण

है कि एफडब्ल्यूजी के कार्य को मात्र तकनीकी कार्य के रूप में नहीं, बल्कि 20 सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की समष्टि आर्थिक नीतियों के बारे में सार्थक बातचीत के लिए और सहकारिता हेतु किए गए प्रयास के रूप में देखा जाए जिसके चलते महत्वपूर्ण नीतिगत समन्वयन होगा जो कि सबके हित में है।

वैश्विक रिजर्व मुद्रा

29. वैश्विक संकट ने अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की क्षमता और विशेष रूप से वैश्विक रिजर्व मुद्रा और तनाव के समय चलनिधि के प्रावधान के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। अभी जो प्रणाली हम अपना रहे हैं उसमें अमरीकी अर्थव्यवस्था की व्यापकता, वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी, विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय लेनदेनों में अमरीकी डॉलर का सबसे अधिक इस्तेमाल होने के कारण अमरीकी डॉलर विश्व की रिजर्व मुद्रा है। और जैसा कि बैरी इशेनग्रीन ने अपनी किताब डॉलर की कहानी³ में उल्लेख किया है कि रिजर्व मुद्रा का स्टेटस रणनीति और सैन्य संबंध, कानून, संस्थान और दायित्व जिसे इन्होंने 'नेटवर्क एक्स्टर्नलिटी' कहा है, पर भी निर्भर करता है।

30. ट्रिफिन पैराडाक्स के समान, अमरीका को राजकोषीय और बाह्य घाटे के साथ रिजर्व मुद्रा जारी करने की औपचारिकाएं पूरी की हैं और साथ ही उसे घाटे को पूरा करने के लिए आवश्यक समायोजन करने की आवश्यकता न होने का 'असीमित अधिकार' भी मिला है। घाटे को कम करने का कोई दबाव न होने के कारण एक प्रबल अर्थव्यवस्था संभवतः वैश्विक स्तर पर असंतुलन पैदा कर सकती है और संभवतः इस संकट का यही कारण था। यह दलील दी जा सकती है कि एकल रिजर्व मुद्रा के संदर्भ में भी, वैश्विक असंतुलन को रोका नहीं जा सकता। यदि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं व्यापार लाभ के लिए या फिर बाह्य आघातों के विरुद्ध स्व-बीमा के उपाय के रूप में रिजर्व आस्तियों को एकत्र करके मांग पक्ष को गति प्रदान नहीं करती तो अमेरिका में लगातर घाटे की स्थिति नहीं रही होती।

31. संकट के दौरान संसार के समक्ष एकल रिजर्व मुद्रा की समस्या सामने आ गई क्योंकि अनेक देशों को डॉलर चलनिधि का सामना करना पड़ा था क्योंकि विदेशी लेनदारों और विदेशी निवेशकों द्वारा तेजी से डिलिवरेजिंग की गई थी। विरोधाभासी रूप से अमरीकी

³ इग्नॉर्बिटंट प्रिविलेज: दि राइज एंड फॉल ऑफ दि डॉलर ऑफ इंटरनैशनल मॉनिटरी सिस्टम-बैरी इशेनग्रीन।

अर्थव्यवस्था भी मंदी की चपेट में होने और इसके केन्द्रीय बैंक द्वारा बहुत अधिक मुद्रा आपूर्ति की जाने के बावजूद फ्लाइट-टू-सेफ्टी के चलते डॉलर मजबूत हो गया।

32. संकट के अनुभव के आधार पर, एकल रिजर्व मुद्रा के कारण होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुधार संबंधी अनेक प्रस्ताव रखे गए हैं। उनमें अनेक वैकल्पिक रिजर्व मुद्राएं दी गई हैं। किन्तु यह किसी आदेश द्वारा नहीं हो सकता। विकल्प के रूप में एक गंभीर प्रतियोगी होने के लिए किसी भी मुद्रा को कुछ सख्त मानदंडों को पूरा करना होता है। यह पूरी तरह से परिवर्तनीय हो और इसकी विनिमय दर बाजार के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए; इसका विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए; मुद्रा जारी करने वाले देश में चल निधियुक्त, खुले और बड़े वित्तीय बाजार होने के साथ-साथ नीतिगत विश्वनीयता भी होनी चाहिए ताकि वह भावी निवेशकों का विश्वास जीत सके। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी रिजर्व मुद्रा का 'असीमित अधिकार' 'असीमित दायित्व' के साथ आता है।

33. एकल रिजर्व मुद्रा का दूसरा समाधान यह है कि एसडीआर को रिजर्व मुद्रा के रूप में विकसित किया जाए। यह सुकर विकल्प नहीं लगता। एक प्रभावी रिजर्व मुद्रा बनने हेतु एसडीआर को अनेक शर्तों को पूरा करना होगा: एसडीआर को आईएमएफ की देयता के रूप में स्वीकारना होगा, यह सीमापारीय लेनदेनों में भुगतान माध्यम के रूप में स्वतः स्वीकार्य होनी चाहिए; इसके मुक्त क्रय-विक्रय की व्यवस्था होनी चाहिए और इसका मूल्य मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होना चाहिए।

34. तीसरा विकल्प यह है कि उन देशों की मुद्राओं को शामिल करके एसडीआर का विस्तार किया जाए जिनका महत्व आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से बढ़ रहा है। उभरते बाजारों के बढ़ते आर्थिक महत्व के कारण यह समझ से परे लगता है कि उभरते बाजार यह नहीं चाहेंगे कि उनकी मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों में अपनी बड़ी भूमिका न निभाए। हाल ही में, कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विशेष रूप से चीन और रूस द्वारा किए गए उपायों का उद्देश्य है कि उनकी मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय इस्तेमाल में आएँ। उभरती बाजार मुद्राओं का बाहर रहना उन्हें प्रणाली का दर्शक बनाता है न कि हिस्सेदार। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में उभरते बाजारों को सम्मिलित करने से प्रणाली की स्थिरता में वे योगदान कर सकेंगे। तथापि, इस विकल्प के पक्ष और विपक्ष दोनों का अध्ययन अभी पूरी तरह से नहीं किया गया है। विशेष रूप से, हमें इस प्रश्न पर ध्यान

देना है कि क्या उभरती बाजार की मुद्राएं, जो कि पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं हैं, एसडीआर में शामिल करने के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा कर सकती हैं।

35. चौथा विकल्प वस्तुतः एक विकल्प नहीं है किन्तु यह समाधान का एक भाग है। इसका उद्देश्य स्व-बीमा की आवश्यकता कम करता है और उसके कारण पहले से प्रबंध की गई ऋण व्यवस्था, जिसका आसानी से और त्वरित लाभ लिया जा सकता है, के बहुपक्षीय विकल्प की सहायता से किसी रिजर्व मुद्रा पर निर्भरता को कम करना है। इसे ध्यान में रखकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋण व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की है।

36. उपर्युक्त में से कोई भी उपाय एकल वैश्विक रिजर्व मुद्रा से उत्पन्न समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं करता। इसका मतलब यह है कि हमें उन अतिसंवेदनशीलताओं से अपने आपको बचाने के लिए इन विकल्पों और अन्य विकल्पों की वैश्विक स्तर पर जांच करने की आवश्यकता है जिनका सामना हम एकल रिजर्व मुद्रा के चलते करते हैं।

37. वैश्विक रिजर्व मुद्रा के बारे में भारत की अपनी स्थिति यह है कि रिजर्व मुद्राओं की संख्या बढ़ाना सुविधाजनक होगा किन्तु इसे स्वयं स्वीकार करना होगा न कि किसी आदेश द्वारा। इस दौरान, देशों को वैश्विक मुद्रा प्रणाली की अतिसंवेदनशीलता से अपने आपको बचाने हेतु रक्षा-कवच की आवश्यकता होगी। साथ ही, अमरीका को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक देश को विशेष रूप से तनाव के समय डॉलर चलनिधि उपलब्ध हो।

38. इस मत के अनुसार, देशों को आरक्षित निधि बनाने से परहेज करने हेतु और पूरी तरह से बाह्य रक्षा-कवच पर निर्भर रहने हेतु नहीं कहा जा सकता। विदेशी मुद्रा भंडार निश्चित रूप से बचाव की पहली पंक्ति होना चाहिए। उसके ऊपर उन्हें मुद्रा स्वैप व्यवस्था की आवश्यकता है। वास्तव में, वैश्विक आरक्षित मुद्रा जारी करने की हैसियत रखने की वजह से भारत सहित सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर स्वैप सुविधा प्रदान करने का अमेरिका का दायित्व उन मुद्दों में से एक है जिसकी चर्चा हमने पिछले महीने मंत्री स्तरीय भारत-अमरीकी बातचीत के दौरान की थी।

संरक्षणवाद

39. संकट के बाद, वस्तुतः 'अवैश्वीकरण' नहीं हो सकता है किन्तु पहले यह मानना था कि वैश्वीकरण पूरी तरह वरदान है

जो कि अब पूरी तरह सही नहीं लग रहा है। वैश्वीकरण की पीछे औचित्य यह था और अभी भी यह मानना है कि भले ही उन्नत देश कम महत्वपूर्ण कार्यों का आउटसोर्स करें, फिर भी उन्हें वैश्वीकरण से लाभ होगा क्योंकि प्रत्येक कम महत्व वाले कार्यों को आउटसोर्स करने के बदले वे अधिक कुशलता वाले, अधिक लाभकारी नौकरियों सृजित कर सकते हैं। यदि यह तेजी से और पर्याप्त रूप से नहीं हुआ, तो संरक्षणवादी दबाव उत्पन्न हो जाएगा और तेजी से प्रभावी और राजनैतिक ढंग से बाध्यकारी बन जाएगा।

40. वैश्वीकरण के भय के बारे में हाल की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों ने 'विडम्बनायुक्त परिवर्तन' होने के संकेत दिए हैं। पहले उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, को भय था कि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होने से उन्हें घरेलू बाजार में नुकसान होगा। अब वही भय उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को सता रहा है कि वैश्वीकरण का मतलब विदेश में उपलब्ध सस्ते श्रम के कारण नौकरियों को खोना है।

41. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, जी 20 के नेता इस बात पर दृढ़ थे कि वे 1930 की घटना को दोहराने नहीं देंगे जब अधिक संरक्षणवादी नीति के चलते महा मंदी और अधिक बढ़ गई थी। तथापि, कई क्षेत्रों में यह चिंता रही है कि भले ही खुली संरक्षणवादिता ने वर्तमान संकट पर अपेक्षाकृत रोक लगाई हो, फिर भी अस्पष्ट संरक्षणवादिता बढ़ रही है। अस्पष्ट संरक्षणवादिता एंटी-डॉपिंग कार्रवाई, रक्षोपाय, बेलआउट पैकेज और पक्षपाती अधि प्राप्ति प्रथाओं में देशी फर्मों को अधिमानी व्यवहार जैसे उपायों से संबंधित समाधान का रूप लेती है। बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दोहा राउंड के निष्कर्षों का महत्त्व बढ़ गया है। ऋण बढ़ाने वाले प्रोत्साहन पैकेजों के बारे में बढ़ती चिंता वाले विश्व में दोहा राउंड समझौते को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गैर-ऋण बढ़ाने वाले प्रोत्साहन के रूप में लिया जाना चाहिए।

42. भारत संरक्षणवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। तथापि, हमें डब्ल्यूटीओ का सम्मान करना है जहां विकासशील देशों के लिए संवृद्धि, विकास, और स्थिरता से संबंधित उनके वैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगत नीति उपलब्ध है। हमें डब्ल्यूटीओ, ओईसीडी तथा यूएनसीटीएडी द्वारा जी 20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर संयुक्त रूप में जारी हाल की व्यापार निगरानी रिपोर्ट के विश्लेषण से प्रोत्साहन मिला है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि समीक्षा अवधि के दौरान भारत द्वारा किए गए व्यापार संबंधी अधिकांश

उपाय या तो व्यापार के लिए सुविधाजनक थे या फिर वापस लिए गए उपाय थे।

आईएमएफ कोटा और अभिशासन

43. 2008 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे और इसके अभिशासन की संरचना की कमजोरियों को प्रकट कर दिया। जी 20 अभिशासन और संरचनागत कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है और साथ ही, पारस्परिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया और नीतिगत सहयोग के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास भी कर रहा है। इन सुधारों का महत्वपूर्ण प्रोत्साहन यह है कि पिछले डेढ़ दशक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तन को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में समुचित ढंग से प्रदर्शित नहीं हुए हैं।

44. जहां प्रमुख सुधार लागू करने के समझौते पर जी 20 में निर्णय हो गया हो, वहीं इनका कार्यान्वयन अभी तक निराशाजनक रहा है। आईएमएफ कोटा और गवर्नेंस रिफार्म 2010 का अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया है। भारत की प्रमुख चिंता यह है कि हमें आईएमएफ कोटा रिफार्म का अनुपालन जनवरी 2013 तक सुनिश्चित करना है ताकि यह कोटा की 15वीं सामान्य समीक्षा का आधार बन सके जिसे जनवरी 2014 के पहले पूरा करना है।

45. इस बात की आलोचना की गई कि आईएमएफ कोटा और गवर्नेंस के मुद्दों का समाधान आईएमएफ के फोरम में किया जाए न कि जी 20 में। यद्यपि, प्रमुख राय यह थी कि जी 20 समग्र मार्ग-दर्शन के लिए प्रमुख फोरम बना रहना चाहिए, न सिर्फ यह निर्देश देने के लिए कि फार्मूला की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे से संबंधित सुधार उपायों को करने के लिए भी बना रहना चाहिए, क्योंकि आंतरिक रूप से और पुरानी शेरधारिता संरचना के चलते सुधार करना मुश्किल है। जी 20 ने पहले भी कोटा फार्मूला पर बहस को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और यदि आगे चलकर यह पहलू इससे अलग कर दिया गया तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

46. वैश्विक संस्थाएं तभी वैध और विश्वसनीय हो सकती हैं जब उनका वोट शेयर और गवर्नेंस संरचना विश्व की अर्थव्यवस्था में सदस्यों के शेयर को प्रदर्शित करें। इस संदर्भ में भारत और अन्य उभरते देशों का मानना है कि जीडीपी का कोटा फार्मूला में प्रभावी

महत्व होना चाहिए क्योंकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में सापेक्षित आर्थिक महत्व का सबसे बड़ा उपाय है।

वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सुधार

47. जैसा कि ज्ञात है कि संकट के दो प्रमुख कारकों में से एक वित्तीय अविनियमन और दूसरा वैश्विक असंतुलन है। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि वित्तीय क्षेत्र के विनियमन से संबंधित सुधारों को जी 20 की कार्यसूची में प्राथमिकता दी गई है।

48. जी 20 के नेतृत्व में वित्तीय क्षेत्र से संबंधित उपायों पर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की विस्तृत रूपरेखा चार स्तम्भों पर खड़ी है: विनियमन, पर्यवेक्षण, संकल्प, विशेष रूप से वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (या एसआईएफआई) के संदर्भ में, और नए मानकों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन। उनमें से एक स्तंभ जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया, वह विनियामक सुधार है, जिसमें नए बासेल III पूंजी और चलनिधि मानकों से संबंधित समझौते सहित पहले भी काफी कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं।

49. तथापि, विनियामक सुधार की प्रक्रिया, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में पहले हो चुकी है, अब नई चुनौती बन गई है विशेष रूप से क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नया जोखिम बना है। अनिश्चित और विषम सुधार के चलते कुछ समूहों ने मांग की है कि वित्तीय सुधार के प्रयास को कम या धीमा किया जाए। वित्तीय क्षेत्र के सुधार को मजबूत करने के लिए सख्त समायोजनों की बैंक लोडिंग के मामले में सुधार के प्रति हमारा संकल्प या प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की कमी भविष्य में एक नए संकट का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए मुख्य कार्य यह है कि जिस पर सर्वसम्मति बनी है उसका भलीभांति कार्यान्वयन किया जाए।

50. जी 20 के सभी सदस्यों ने बासेल III पैकेज के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। तथापि, प्रमुख देशों ने अपने खुद के विनियामक मानदंड बनाए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई मतभेद नहीं है जिसमें हम उलझ सके। हमें विनियामक विवाचन की संभावना के विरुद्ध सुरक्षा करने की आवश्यकता है। यदि एक साथ सभी देशों में इन तुलनीय मानदंडों का कार्यान्वयन नहीं किया गया तो संभवतः वित्तीय गतिविधियां कम विनियमित देशों और शैडो बैंकिंग की ओर चली जाएंगी जिससे संपूर्ण वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी।

51. हम जैसे ही विनियमन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश की आवश्यकता

पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। इस संबंध में दो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। पहला, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं नए विनियामक ढांचे में अलाभप्रद न हों क्योंकि उनकी प्रणाली में अवसर और चुनौतियां पूरी तरह से भिन्न होती हैं।

52. दूसरा, अधिक मांग वाले विनियामक मानदंडों के चलते उभरते बाजारों में से वैश्विक वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिलिवरेजिंग नहीं की जानी चाहिए। इस संबंध में यह देखा जाना चाहिए कि वित्तीय विनियामक सुधार का जोर अभी तक प्रणालीगत जोखिम को कम करने पर रहा है और वास्तविक अर्थव्यवस्था में निवेश को वित्त पोषण करने के लिए अस्थिर वित्तीय आस्तियों में निवेश से बचत की ओर पुनःप्रेषित करने के लिए बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है जहां संवृद्धि और रोजगार पर प्रभाव अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता है। इस बात को पहचानने की आवश्यकता है कि यह वास्तविक क्षेत्र से प्राप्त वह आय है जो वित्तीय क्षेत्र के लाभ के लिए अंततः चुकाई जानी चाहिए। मानक निर्धारण करने वाले निकायों को इस प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं बनानी चाहिए जो वैश्विक बचत को वास्तविक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर, मांग समर्थन में निवेश की ओर ले जाएं और वास्तविक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और विकास के लिए मध्यवर्ती संस्था की मूल भूमिका को पूरा करने के लिए दीर्घावधि संभाव्य संवृद्धि को बढ़ाएं।

53. वित्तीय प्राधिकारियों के बीच इन मुद्दों पर सहयोग बहुत ही जरूरी है, यद्यपि यह थोड़ा मुश्किल और कठिनाई भरा कार्य है। सहयोग उस समय अधिक मुश्किल हो जाता है जब अस्थिर वित्तीय बाजारों और कम संवृद्धि की स्थिति में बड़े वित्तीय बदलाव अपरिहार्य हो जाते हैं। फिर भी, ये वही चुनौतियां हैं जो इसको इतना महत्वपूर्ण बना देती हैं कि जी 20 में विनियामक प्रतिक्रिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक समन्वयपूर्ण होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नया विनियामक ढांचा प्रभावशाली है और इसका कार्यान्वयन वैश्विक स्तर पर किया गया है और जिन कारणों के चलते वित्तीय संकट पैदा हुआ था उन्हें फिर से न दोहराया जाए।

जी 20 के लिए भावी चुनौतियां

54. मैंने अभी तक जी 20 की कार्यसूची से संबंधित प्रमुख मुद्दों के बारे में चर्चा की है। मैं अब जी 20 के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा करूंगा।

55. पहली चुनौती अल्पावधि अनिवार्यता और मध्यावधि वहनीयता के बीच में संतुलन से जुड़ी है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय मितव्ययिता बनाम संवृद्धि मजबूती बहस का प्रमुख मुद्दा है। इस बात पर सभी सहमत हैं कि दीर्घावधि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण समष्टि आर्थिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ, अल्पावधि के दौरान राजकोषीय समायोजन से होने वाली कठिनाइयों से भी सभी परिचित हैं। यदि राजकोषीय अपव्यय को भावी आय की खपत और भावी पीढ़ी पर भार अंतरण के रूप में लिया जाए तो राजकोषीय मितव्ययिता को आवश्यक सुधार के मूल्य के रूप में देखना चाहिए ताकि सभी पीढ़ियों में भार का बंटवारा उचित हो। यदि अल्पावधि और दीर्घावधि नीतियों की अनिवार्यताएं भिन्न-भिन्न हैं तो इनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है विशेष रूप से जब दीर्घावधि अल्पावधि के साथ जुड़ी होती हैं। जी 20 की प्रतिबद्धताएं और 'पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया' (एमएपी) की प्रतिबद्धताएं और मूल्यांकन इस प्रकार के गतिशील नीतिगत बदलावों को कैसे शामिल कर सकते हैं?

56. जी 20 के समक्ष दूसरी चुनौती देशों की नीतियों को पारस्परिक सहमति की ओर ले जाना और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर देशों को जिम्मेदार मानने की है, विशेष रूप से क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं और न ही इसका कोई प्रवर्तन तंत्र है। विशेष रूप से यह शक्तिशाली प्रजातंत्रों में मुश्किल है जहां लोकप्रिय नजरिया यह हो सकता है कि वैश्विक स्थिरता के लिए राष्ट्रीय हित के साथ समझौता न किया जाए। राष्ट्रीय नेता अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एक वैश्विक हित के वातावरण का निर्माण और उसका पोषण किस प्रकार सकते हैं?

57. दृढ़, भावी प्रतिबद्धता की मांग या यूरोपीय संघ या ओईसीडी की कार्य-शैली पर आधारित अन्य देशों के नीतिगत ढांचे की स्पष्ट आलोचना इस समय मुश्किल और मतभेदपूर्ण हो सकती है। वैश्विक अभिशासन की अधिक महत्त्वांक्षी प्रणाली को विकसित होने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। इस समय, प्रमुख मुद्दा इस बात की निगरानी और मूल्यांकन का है कि क्या जी 20 के सदस्य देशों की नीतियों की सामान्य दिशा मध्यावधि से दीर्घावधि के दौरान पारस्परिक ढंग से लगातार और सहमति की ओर बढ़ रही है और जी 20 की प्रक्रियाएं देशों को उनके देशी विधान, विनियामक और न्यायिक प्रक्रियाओं में सामंजस्य ला सकती हैं जिससे सामान्य रूप से सहमत नीतियां स्वीकार की जा सकती हैं।

58. जी 20 के समक्ष तीसरी चुनौती यह है कि नीति और बाजार विस्तार के साथ लगातार वैश्वीकृत होते विश्व में देशी नीतिगत कार्रवाईयों की सफलता वैश्विक परिणामों से जुड़ी हैं। यदि पुनःसंतुलन में समन्वयन नहीं होगा तो परिणाम इससे भी खराब हो सकते हैं। इसलिए, नीतिगत सहयोग भावी सफलता है क्योंकि राजनैतिक एकीकरण की तुलना में आर्थिक एकीकरण में कहीं अधिक विस्तार हुआ है। यह यूरो जोन के मामले में बहुत अधिक स्पष्ट दिखायी देता है, जी 20 के समक्ष चुनौती काफी हद तक यूरो जोन के समान ही है। इस संबंध में, जी 20 को सहयोग का लाभ लेने के लिए वैश्वीकरण का विस्तार करने के संदर्भ में एक सहासी प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है।

सारांश और समापन

59. अब मैं समापन करता हूँ। मैंने अपनी बात जी 20 के महत्त्व और वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने में इसे प्राप्त विश्वसनीयता का उल्लेख करते हुए शुरू की थी। मैंने संकट के बाद के मुद्दों का सावधानीपूर्वक समाधान करने में असफल प्रतीत होने पर जी 20 की आलोचना भी की। उसके बाद, मैंने जी 20 की कार्यसूची की प्रमुख

मद्दों पर चर्चा की और जहां मुझे आवश्यक लगा वहां इन मुद्दों पर भारतीय स्थिति के बारे में भी चर्चा की। मैंने जी 20 के प्रयोग के लिए भावी तीन बड़ी चुनौतियों को सूचीबद्ध किया।

60. जी 20 सभी प्रकार से एक साहसी पहल है। यह पूर्व के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से इस आशय से अलग है कि इसका गठन किसी चार्टर द्वारा नहीं किया गया और न ही वैश्विक गवर्नेंस हेतु कोई अधिदेश है और न ही इसमें लिए गए निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी हैं। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि यह इस धारणा पर आधारित है कि वैश्वीकृत विश्व में हमारा भविष्य सभी के साथ जुड़ा है जिसके जरिए हम प्रगति कर सकते हैं, वह रास्ता नीतिगत सहयोग से होकर जाता है और इस विश्वास पर आधारित है कि वैश्विक गवर्नेंस का पालन सम्मान संहिता के जरिए किया जा सकता है।

61. क्या जी 20 का अस्तित्व बना रहेगा? स्वर्गीय श्री श्राफ ने क्या कहा होता? वे यथार्थवादी थे। अतः उन्होंने कहा होता कि जी 20 का अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब वह हमारी अत्यधिक तनावपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने में वैश्विक स्तर पर आदर्श नेतृत्व प्रदर्शित करे।